# बिहार में बनेंगे दस लाख निजी शौचालय

हिन्दुस्तान 18-12-13

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

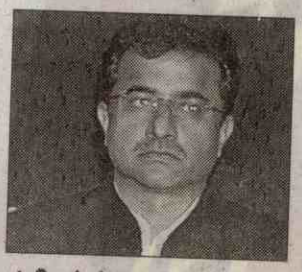

## मंत्री बोले

- शौचालय निर्माण के लिए देय राशि बढ़ाकर दस हजार रुपये की जाएगी
- ग्रामीण विकास विभाग की विजिलेंस एंड मानिटरिंग कमेटी की हुई बैठक

बिहार में सरकारी सहायता से इस वित्तीय वर्ष में दस लाख निजी शौचालय बनाये जाएंगे। शौचालय निर्माण के लिए धन की निर्धारित सीमा बढ़ाई जाएगी। सूबे के विभिन्न क्षेत्रों में 42 हजार शौचालयों का निर्माण शुरू हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र और सचिव अमृतलाल मीणा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वह विभाग की ओर से आयोजित स्टेट विजिलेंस एंड मानिटरिंग कमेटी की बैठक में मौजूद थे। बैठक में सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब शौचालय के निर्माण के लिए दस हजार रुपए लाभान्वितों को मिलेंगे। इस संबंध में सरकार शीघ्र फैसला लेगी। नए नियम के तहत निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले सभी जाति व सभी श्रेणियों के लोगों को यह राशि मिलेगी। इसमें बीपीएल श्रेणी आदि कोई बाध्यता नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही अलग ग्रामीण विकास सेवा को विकसित करेगी। बीपीएससी के माध्यम से ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग में 520 पदाधिकारियों का चयन किया जा चुका है। उन्हें अभी प्रशिक्षण में भेजा गया है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें जल्द ही महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इसके आलावा इंदिरा आवास योजना में मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। इस योजना के तहत बन रहे आवास की कम से कम चार बार फोटोग्राफी होगी। पंचायत स्तर पर लेखापाल की स्थायी व्यवस्था की जाएगी।

पंचायतों में निर्माण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए अलग इंजीनियरिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मनरेगा कार्यों के लिए चार हजार रिक्तियों पर अगले माह तक भर्तियां कर ली जाएंगी। बैठक में समाज कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के काम की समीक्षा की गई। सदस्यों की मांग पर कार्यान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण और क्षेत्र भ्रमण के लिए जनवरी माह के दूसरे सप्ताह का चुनाव किया गया। इस मौके पर सदस्य समीर कुमार महासेठ ने विकलांगता पेंशन का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रखंड स्तर पर चिकित्सकों की तैनाती व कैम्प लगाने का सुझाव दिया। ताकि विकलांग बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा सके।